(ख) इन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये कितनी धनराशि मंजूर की गई है; और

(ग) इन योजनाओं को कब तक क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायगी ।

राजस्थान में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई

2535. **श्री मीठा लाल मीना** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था करने के लिये सरकार ने कौन-कौन सी योजनाएं बनाई हैं;

(ख) इन योजनाओं की क्रियान्विति के लिये कितने धन की मंजूरी दी गई है; और

(ग) ये योजनाएं कब तक क्रियान्वित हो जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) :(क) से (ग). राजस्थान में 223 करोड़ रुपये की अनुमति लागत की 35 बड़ी और मंझली सिंचाई स्कीमों की कार्यान्विति हो रही है । इन परियोजनाओं पर मार्च, 1967 के अन्त तक 133 करोड़ रुपये खर्च हुए। पूर्ण हो जाने पर इन परियोजनाओं से 33 लाख एकड़ भूमि को लाभ पहुंचेगा । मार्च, 1967 के अन्त तक परियोजनाओं द्वारा लगभग 16 लाख एकड़ की शक्यता पैदा की गई, जिसमें से लगभग 12 लाख एकड़ का उपयोग हुआ । आशा है कि चौथी योजना के दौरान ये परियोजनाएं काफी पूर्ण हो जायेंगे ।

जहां तक लघु सिंचाई स्कीमों का सम्बन्ध है, राजस्थान सरकार ने 1965-66 और 1966-67 के दौरान लगभग 8 करोड़ रुपये खर्च किये । 1967-68 के लिये 2.87 करोड़ रुपये का व्यय स्वीकार किया गया है । राजस्थान सरकार ने अभावग्रस्त क्षेत्रों में 250 नलकूप लगाने की एक स्कीम भी शरू की है । इन में से अभी तक लगभग 196 नलकूप सफलतापूर्वक लगाए जा चुके हैं ।

महाराष्ट्र के लिये बाढ़-नियंत्र योजनायें

2536 **श्री देवराव पाटिल** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967-68 में महाराष्ट्र में बाढ़ नियन्त्रण, पानी को निकालने तथा पानी को जमा न होने देने के लिये कोई धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) क्या पान गंगा नदी में आने वाली बाढ़ पर पूर्ण नियन्त्रण के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई दीर्घकालीन योजनायें बनाई गई हैं तथा मंजूर हो चुकी हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जल-निकास तथा जल अभाव रोधी स्कीमों समेत, स्वीकृत बाढ़-नियंत्रण स्कीमों पर धन लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार को 1967-68 के दौरान 2 लाख रुपये की राशि केन्द्रीय ऋण सहायता के रूप में आवंटित की गई है ।

(ख) और (ग). पान गंगा नदी में बाढ़ों के नियन्त्रण के लिये महाराष्ट्र सरकार से अभी तक कोई दीर्घकालीन स्कीम प्राप्त नहीं हुई है ।